

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2943
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

किसानों की स्वामित्व वाली भूमि

2943. श्री शेर सिंह घुबाया:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की भूमि पर लम्बे समय से काम कर रहे किसानों को स्वामित्व का अधिकार देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह अधिकार कब तक मिलने की संभावना है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो० एस० पी० सिंह बघेल)

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की भूमि पर काम करने वाले किसानों को स्वामित्व का अधिकार सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की भूमि पर लंबे समय से काम कर रहे किसानों को स्वामित्व का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये साहुलियत दी गई है कि वे ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दे सकें। 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली इस योजना में अब तक 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण का कार्य लगभग 93% तक पूरा हो चुका है।
